

समक्ष एमएम पुंची जे.

राम फल- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य— प्रतिवादी

आपराधिक' रिट याचिका 1985 की सं. 394

23 मई 1985

भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 161- सजा माफी के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा इसके तहत प्रख्यापित आदेश- पंजाब जेल मैनुअल- पैराग्राफ 631 से 650- कारागार अधिनियम (1894 का 9)-धारा 2- मंत्री की यात्रा की तारीख से पहले दोषी ठहराए गए लेकिन बाद में जमानत पर रिहा किए गए कैदी राज्य सरकार के आदेशों के तहत माफी के हकदार हैं, यदि वे अपनी सजा के शेष हिस्से को भुगतने के लिए जेल में आत्मसमर्पण करते हैं - ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए लेकिन उसी दिन जमानत पर रिहा किए गए कैदी - अपील लंबित रहने के दौरान जमानत जारी रहेगी। उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका- पुनरीक्षण याचिका खारिज- पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के काफी समय बाद दोषी को हिरासत, गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में लिया गया- जब दोषी जमानत पर था तब जेल मंत्री का जेल दौरा- ऐसा दोषी- क्या क्षमा का हकदार है- समर्पण- का अर्थ।

आयोजित, उच्च न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी करने का उपक्रम किया जाता है और उसकी प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, तो दोषी से यह अपेक्षा करना उचित

है कि वह स्वेच्छा से जेल अधिकारियों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे और अदालत के फैसले के आगे झुक जाए। तभी यह संभव है। यह कहा जा सकता है कि उसने समय पर और स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह सजा की ऐसी छूट का लाभ उठा सके, जो उसने अर्जित किया होता यदि वह जेल में होता और जमानत पर नहीं होता, जब राज्यपाल या मंत्री ने जेल का दौरा किया, जहां उसे कैद किया जाना चाहिए था। अदालत के फैसले के साथ रखे जाने पर सरकारी आदेशों की भावना, इरादे और उद्देश्य को प्रभावित करने का यही एकमात्र तरीका प्रतीत होता है। जैसा कि अभिव्यक्ति से स्पष्ट है 'छूट केवल तभी दी जाएगी जब वे अपनी सजा का शेष भाग भुगतने के लिए जेल में आत्मसमर्पण करेंगे', माफी आत्मसमर्पण के साथ जुड़ी हुई है। अनिवार्य रूप से, इसे स्वैच्छिक और समय पर समर्पण करना होगा। किसी भी तर्क से यह नहीं माना जा सकता कि न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा पुनः गिरफ्तारी परिकल्पना के अनुसार आत्मसमर्पण करने के समान है; समान रूप से, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अपनी पसंद के समय पर समर्पण कर सकता है - चाहे वह कितना भी दूरस्थ और दूर का समय क्यों न हो। 'समर्पण' का अर्थ है 'खुद को समर्पित करना' जो अनिवार्य रूप से एक स्वैच्छिक और स्पष्ट रूप से समय पर किया जाने वाला कार्य है। किसी दोषी द्वारा विलंबित आत्मसमर्पण स्पष्ट रूप से न्याय प्रशासन में बाधा और हस्तक्षेप करेगा। किसी की सुविधानुसार जेल जाना या न जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रख्यापित सरकारी आदेशों के संदर्भ से अलग है। जेल की सज़ा कोई व्यावसायिक कवायद या कर्ज़ नहीं है जिसे कोई जब भी सुविधाजनक चुका सकता है। यदि समाज की मांग यह है कि न्याय शीघ्र होना चाहिए, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि अदालत का फैसला शीघ्र आना चाहिए। इसका क्रमिक अर्थ यह है कि वाक्य को तार्किक गति से क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार, यह अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए कि सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए दोषी द्वारा जेल में आत्मसमर्पण, स्वेच्छा से और बिना किसी हिचकिचाहट के, अदालत के आदेश के करीब होना चाहिए।

(पैरा 4, 5 एवं 7)

अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिका भारत के संविधान की धारा 226 में प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि मामले के रिकार्ड का तलब करने और अवलोकन के बाद:-

- (i) *बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट याउत्तरदाताओं को हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने का आदेश देते हुए परमादेश जारी किया जाए।*
- (ii) *कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, जारी किया जाएगा।*
- (iii) *याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाए।*

याचिकाकर्ता के वकील बी. एस. मलिक।

केएस सैनी, वकील, ए. जी. हरियाणा।

निर्णय

एमएम पुंछी, जे.

(1) क्या जमानत पर रहते हुए अनुपस्थिति में किया गया जेल की सजा में छूट का दावा जमानत पर छूटे कैदी के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण पर निर्भर है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस आपराधिक रिट याचिका में विचार के लिए सामने आया है।

कथित बंदी राजिंदर कुमार पर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा

16(1)(a)(i) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। उन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद की अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया और 22 अक्टूबर, 1981 को सजा सुनाई गई। उसी दिन, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिससे वह सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सके। अपील दायर होने पर 21 दिसंबर, 1982 को खारिज कर दी गई। उसी दिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष 1983 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 55, 18 जनवरी, 1983 को दायर की, उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद की संतुष्टि के लिए इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। अपेक्षित बांड निष्पादित होने पर, उन्हें वास्तव में 32 दिनों की सजा भुगतने के बाद 21 जनवरी, 1983 को जेल से रिहा कर दिया गया था। 14 फरवरी, 1984 को इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन कारावास की सजा को घटाकर छह महीने के कठोर कारावास में बदल दिया गया। इस न्यायालय से मंत्रिस्तरीय पुनः गिरफ्तारी आदेश 22 मार्च, 1984 को सत्र न्यायाधीश, जींद को जारी किया गया था और फैसले और औपचारिक आदेश की एक प्रति, दिनांक 14 फरवरी, 1984 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद को भी जारी की गई थी। अनुपालन के लिए आवश्यक है कि राजेंद्र कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनकी सजा की शेष अवधि भुगतने के लिए जेल भेजा जाए और इस न्यायालय द्वारा 18 जनवरी, 1983 को जारी किया गया जमानत आदेश निरस्त कर दिया जाए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 मार्च, 1985 को पुलिस द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस डेटा से यह स्पष्ट है कि 14 फरवरी, 1984 को इस न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के बाद बंदी लगभग 13 महीने तक बड़े पैमाने पर रहा और शेष

सजा भुगतने के लिए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं किया। अपनी पुनः गिरफ्तारी पर, यह याचिका राम फल नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई है, जिसमें बंदी में अपनी रुचि का खुलासा किए बिना, यह दावा किया गया है कि बंदी ने इस बीच कुल 180 दिन (6 महीने) की दो विशेष छूट अर्जित की थी और इस प्रकार 12 मार्च, 1985 को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत का कार्य और/या उसके बाद जारी रखा गया हिरासत मौलिक- संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अधिकारों के तहत अवैध था और उसके अधिकार का उल्लंघन था। इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश की प्रकृति की एक रिट के लिए प्रार्थना की गई है।

(2) जेल महानिरीक्षक, हरियाणा ने अपने हलफनामे और अतिरिक्त हलफनामे में सामग्री रखकर या रिकॉर्ड करके बंदियों के दावे का खंडन किया कि जब भी विशेष छूट दी जाती है, तो पहले से ही जमानत पर मौजूद व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित होता है, यदि वे सजा भुगतने के लिए तुरंत जेल में आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनकी सजा का शेष भाग, न कि तब जब राज्य के प्रयास से दोषी को इस उद्देश्य के लिए पुनः गिरफ्तार किया गया हो।

(3) विवाद की सराहना करने के लिए, इस विषय पर लागू कानून और नियमों का जायजा लेना समझदारी होगी। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, किसी राज्य के राज्यपाल को उस मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा में छूट देने या सजा को माफ करने का अधिकार है, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग किया और क्रमशः 18 जनवरी, 1982 और 3 अक्टूबर, 1983 को दो आदेश, अनुलग्नक R. 1 और R. 2 जारी किए। जिसके प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं: -

अनुलग्नक R-1

हरियाणा के राज्यपाल का आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के कैदियों को सजा में विशेष छूट देते हैं, जो कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए प्रत्येक के खिलाफ नोट की गई सीमा तक है। हरियाणा में और जिला जेल, भिवानी/रोहतक/हिसार, बोस्टल जेल, हिसार, सेंट्रल जेल, अंबाला, जिला जेल, कामा में बंद हैं और जिला जेल, गुड़गांव क्रमशः 28 दिसंबर, 1981, 31 दिसंबर, 1981, 1 जनवरी, 1982, 5 जनवरी, 1982 और 8 जनवरी, 1982 को जेल मंत्री, हरियाणा की उपरोक्त जेलों की यात्रा के अवसर पर: -

- (1) जो कैदी 2 साल से कम की सजा काट रहे हैं, उन्हें 15 दिन तक की सजा हो सकती है
- (2) ऐसे कैदी जो 2 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक की सजा काट रहे हैं, उन्हें 1 महीने तक की सजा हो सकती है
- (3) जो कैदी 7 साल से ज्यादा की सजा काट रहे हैं, उन्हें 2 महीने तक की सजा हो सकती है
- (4) वे सभी कैदी जिन्हें संबंधित जेलों में माननीय मंत्री की यात्रा की उपरोक्त तारीखों से पहले दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, वे छूट के हकदार होंगे, यदि वे अपनी सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए जेल में आत्मसमर्पण

करते हैं।

(5) * *

(6) * *

अनुलग्नक R-2

हरियाणा के राज्यपाल के आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन, हरियाणा के राज्यपाल उन कैदियों को 4 महीने की सजा की विशेष छूट देते हैं, जिन्हें हरियाणा में स्थित विभिन्न न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया था और बोरस्टल में कैद किया गया था। 14 अगस्त, 1983 को जेल मंत्री, हरियाणा के उपरोक्त जेलों के दौरे के अवसर पर जेल, हिसार और सेंट्रल जेल, हिसार: -

वे सभी कैदी जिन्हें संबंधित जेलों में माननीय मंत्री की यात्रा की उपरोक्त तारीखों से पहले दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, वे छूट के हकदार होंगे, यदि वे अपनी सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए जेल में आत्मसमर्पण करते हैं।

अगर अंग्रेजी भाषा के अनुसार कहें तो जेल की भाषा में 'रिमिशन' शब्द का मतलब 'क्षमा' या 'माफी' समझा जाता है। 'संकल्पना स्वयं दया-करुणा के तत्व का सुझाव देता है। स्वाभाविक रूप से, यह क्षमा या माफी के किसी भी अधिकार के प्रतिकूल है।

फिर भी, एक अलग संदर्भ में, विशेष रूप से जेल अधिनियम, 1894 और उसके

तहत बनाए गए नियमों में, कुछ ऐसा है जिसे आसानी से व्यवस्थित छूट कहा जा सकता है। और इसे तब स्पष्ट किया जाता है जब यह कैदी अधिनियम, 1900 के प्रावधानों के साथ सह-संबंधित होता है। जेल अधिनियम की धारा 2 में, 'दोषी आपराधिक कैदी' को अदालत या न्यायालय की सजा के तहत किसी भी आपराधिक कैदी के रूप में परिभाषित किया गया है। मार्शल और इसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1882 (अब 1973) के अध्याय-आठवें के प्रावधानों या कैदी अधिनियम, 1871 (अब 1900) के तहत जेल में हिरासत में लिया गया व्यक्ति शामिल है। परिभाषा में एक दोषी आपराधिक कैदी के मामले को शामिल किया गया है, जो सजा काट रहा है या जेल में निरुद्ध सजा काट चुका है। इसके अलावा, अभिव्यक्ति 'छूट प्रणाली' को उस समय लागू नियमों के रूप में परिभाषित किया गया है जो जेल में कैदियों को अंक देने और उसके परिणामस्वरूप सजा कम करने को विनियमित करते हैं। छूट प्रणाली नियमों के एक सेट के अनुसार काम करती है। जहां तक उस क्षेत्र का सवाल है जिस पर यह न्यायालय अधिकार क्षेत्र लागू करता है, ये पंजाब जेल मैनुअल के अध्याय-XX में पैराग्राफ 631 से 650 में उपलब्ध हैं। 'छूट प्रणाली' के नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन सामने आता है एक दोषी को कैसे छूट अर्जित की जा सकती है। ऐसे मामले हैं जिनमें सामान्य छूट अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, साथ ही जेल में प्रवेश के बाद जेल अपराध करने वाले दोषी को भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। छूट प्रणाली को निलंबित करने और पुनः प्रवेश पर उन्हें सक्रिय करने के भी नियम हैं। छूट के पुरस्कार के पैमाने के लिए नियम हैं जो कैदी के अच्छे आचरण और जेल के सभी नियमों के साथ-साथ उद्योग के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान देने और लगाए गए दैनिक कार्य के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। जब कोई कैदी अपने नियंत्रण से परे कारणों से काम करने में असमर्थ होता है तो नियम माफी के पुरस्कार के

पैमाने को भी निर्धारित करते हैं। सिस्टम के नियमन के लिए और उस समय और अवधि के लिए अन्य नियम मौजूद हैं जब छूट अर्जित की जाती है। दोषी द्वारा विशेष सेवा प्रदान करने पर विशेष छूट अर्जित की जा सकती है। ये अनुच्छेद 644 में प्रदान किए गए हैं। इसमें, अधीक्षक, जेल, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और जेल महानिरीक्षक द्वारा बाहरी सीमा के अधीन विशेष छूट भी दी जा सकती है। इन अर्जित छूटों या विशेष छूटों की एक बाहरी सीमा होती है, क्योंकि स्थानीय सरकार की विशेष मंजूरी के बिना किसी कैदी को दी गई कुल छूट उसकी सजा के एक-चौथाई हिस्से से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत ही असाधारण और उपयुक्त मामलों में, महानिरीक्षक जेलें कुल सजा के एक-तिहाई से अधिक की छूट नहीं दे सकती हैं। इस प्रकार इन नियमों को पढ़ने से स्पष्ट है कि छूट प्रणाली जेल में कैदियों की सजा को कम करने और उसके परिणामस्वरूप अंक देने को नियंत्रित करती है, जो मुख्य रूप से उनके स्वयं के आचरण और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से प्राप्त अनुमोदन पर निर्भर करती है। जेल अधिनियम के तहत पदाधिकारी होने के बावजूद, ये अधिकारी छूट प्रणाली पर काम करने के लिए सशक्त हैं, लेकिन किसी भी तरह से यह नहीं माना जा सकता है कि उन्हें किसी कैदी को क्षमा या माफी की शक्ति प्रदान की गई है। वह शक्ति स्वाभाविक रूप से, संवैधानिक रूप से और उचित रूप से उपयुक्त राज्य सरकार में निहित है और संविधान के प्रावधानों के तहत, राज्यपाल या मंत्री की जेल की औपचारिक यात्राओं पर इसका प्रयोग किया जाता है, हालांकि मनोरंजक रूप से भारत सरकार - पत्र संख्या 27/17/64 दिनांक 1 जुलाई, 1966 के अनुसार - ने राज्य सरकारों को 'निम्नलिखित शब्दों में सावधान किया है: -

“इस तरह की विशेष छूट देने से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप होता है क्योंकि यह जेल में उनके आचरण और व्यवहार के बावजूद सभी कैदियों

की सजा को अनावश्यक रूप से कम कर देता है। ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यपाल या किसी मंत्री की जेल की औपचारिक यात्राओं के संबंध में कैदियों को सजा में विशेष छूट देने की प्रथा वांछनीय प्रथा नहीं है। भारत सरकार का मानना है कि कैदियों को इस तरह की विशेष छूट देने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

फिर भी यह प्रथा बदस्तूर जारी है। यह पूर्व में निकाले गए अनुलग्नक आर-1 और आर-2 से प्रतिबिंबित होता है। अब यदि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत एक विशेष छूट, जेल में कैदियों के आचरण और व्यवहार की अनदेखी करते हुए, क्षमा और क्षमा के तत्व से गर्भवती है, तो जाहिर तौर पर यदि क्षमा या माफी का साधन, शर्तें लगाता है, तो इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए और नहीं। जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के पास उदारतापूर्वक होगा। सज़ाएँ अब प्रतिशोधात्मक नहीं हो सकती हैं और सुधारात्मक हो सकती हैं, लेकिन इन कारकों को राज्य द्वारा अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में दी गई छूट के स्पष्ट साधनों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि अभिव्यक्ति से स्पष्ट है 'छूट केवल तभी दी जाएगी जब वे अपनी सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए जेल में आत्मसमर्पण करेंगे', छूट आत्मसमर्पण के साथ जुड़ी हुई है। अनिवार्य रूप से, इसे स्वैच्छिक और समय पर समर्पण करना होगा। किसी भी तर्क से यह नहीं माना जा सकता कि न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा पुनः गिरफ्तारी परिकल्पना के अनुसार आत्मसमर्पण करने के समान है। समान रूप से, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अपनी पसंद के समय पर दूरस्थ और सुदूर समर्पण कर सकता है। 'समर्पण' का अर्थ है 'खुद को समर्पित करना' जो अनिवार्य रूप से एक स्वैच्छिक और स्पष्ट रूप से समय पर किया जाने वाला कार्य है। किसी दोषी द्वारा विलंबित आत्मसमर्पण स्पष्ट रूप से न्याय प्रशासन में बाधा और हस्तक्षेप

करेगा। किसी की सुविधानुसार जेल जाना या न जाना, 'आर-1 और आर-2' आदेशों के संदर्भ से अलग है। जेल की सज़ा कोई व्यावसायिक कवायद या कर्ज़ नहीं है जिसे कोई उतार सके जब भी सुविधाजनक हो। यदि समाज की मांग यह है कि न्याय शीघ्र होना चाहिए तो इसका मतलब केवल यह नहीं है कि अदालत का फैसला शीघ्र आना चाहिए। इसका क्रमिक अर्थ यह है कि वाक्य को तार्किक गति से क्रियान्वित किया जाता है।

(5) दिलचस्प बात यह है कि इस न्यायालय से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई या दी गई सजाओं में से कई दोषियों को अब तक दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। वर्ष 1965 और 1968 (दोषियों की संख्या अलग) का एक-एक मामला है। इसी तरह, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 1969 के 3 मामले, 1970 के 7 मामले, 1971 के 12 मामले, 1972 के 19 मामले, 1973 के 23 मामले, 1974 के 19 मामले, आईएस 1975 के 19 मामले, 1976 के 7 मामले, 28 1977 के मामले, 1978 के 66 मामले, IS 1979 के 110 मामले, 1980 के 90 मामले, 1981 के 58 मामले, 1982 के 65 मामले, 1983 के 188 मामले, 1984 के 83 मामले और 1985 के 67 मामले हैं। इन सभी मामलों में बीते वर्षों में कल्पना कीजिए। राज्यपालों और मंत्रियों ने जेल का दौरा किया होगा और ऐसे दौरों के अवसर पर विशेष छूट दी होगी। यह कल्पना पर छोड़ दिया गया है कि यदि ढेर सारी विशेष छूटों को 'स्वैच्छिक आत्मसमर्पण' के लिए बाध्य नहीं किया गया है, तो पुनः गिरफ्तारी से सफलतापूर्वक बचने वाले दोषियों ने जेल की सीमा से बाहर रहते हुए अपनी सजा काट ली होगी। बढ़िया गणना गिरफ्तारी-चोरी का कारण हो सकती है। तो फिर त्वरित न्याय कहाँ जाता है? क्षमा और क्षमा पाने वाला कहाँ है? इन कारकों और कोणीयताओं के आधार पर, अनिवार्य रूप से यह माना जाना चाहिए कि दोषी द्वारा अपनी

सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए जेल में आत्मसमर्पण, स्वेच्छा से और बिना किसी हिचकिचाहट के, अदालत के आदेश के करीब होना चाहिए।

(6) जेल महानिरीक्षक द्वारा सामने लाया गया एक दिलचस्प उदाहरण तुही राम का मामला था, जिसे 7 मार्च, 1974 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह 22 दिनों तक जेल में रहा और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष उसकी अपील पर निर्णय होने तक उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी अपील पर 13 जनवरी, 1978 को फैसला सुनाया गया और सजा को घटाकर 2 साल के कठोर कारावास में बदल दिया गया। दोषी ने अपनी अपील के निपटारे के लगभग 6 साल बाद 8 दिसंबर, 1983 को जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। कारा महानिरीक्षक, हरियाणा ने इसे न्याय प्रशासन का मजाक बताया और मेरी नजर में यह सही भी है। क्या किसी भी तर्क से कभी यह कहा जा सकता है कि दोषी, आत्मसमर्पण से बचने या गिरफ्तारी से बचने के दौरान, अनुपस्थिति में विशेष जेल छूट का हकदार बन गया? जाहिर तौर पर इसका उत्तर नकारात्मक होगा।

(7) हमारी अदालती प्रक्रिया के कामकाज पर भी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ट्रायल मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीशों के समक्ष, अभियुक्त की उपस्थिति आम तौर पर हर सुनवाई में सुरक्षित और सुनिश्चित की जाती है और जिस दिन सजा सुनाई जाती है उस दिन वह सजा पाने के लिए उपलब्ध होता है। उसे आम तौर पर जेल भेज दिया जाता है, जब तक कि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय में अपील दायर करें और वह भी समय से सीमित है। जब इस न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण अधिकतर सक्षम वकील के माध्यम से और जेल से थोड़ी संख्या में दायर किया जाता है, तो याचिकाएं, यदि स्वीकार की जाती हैं, तो दोषी की जमानत पर क्रमिक

रिहाई का आदेश दिया जाता है, जो आम तौर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए संबंधित जिला होता है। अपील या पुनरीक्षण की अंतिम सुनवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 385, 386 और 388 के तहत विनियमित होती है। इसे बुलाए गए मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन और अपीलकर्ता या उसके वकील, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक, यदि वह उपस्थित होता है, को सुनने के द्वारा विनियमित किया जाता है। उच्च न्यायालय का निर्णय तब उस न्यायालय को दिया जाता है जिसके निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील/याचिका की गई थी ताकि न्यायालय निर्णय और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप आदेश दे सके और, यदि आवश्यक हो, तो रिकॉर्ड तैयार कर सके। उसके अनुसार संशोधन किया जाए। लेकिन अपील की सुनवाई के संबंध में सूचना, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 385 के तहत परिकल्पित है, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड-V, अध्याय 3-ए, नियम 5 के तहत विनियमित है। इस फैसले पर विस्तार से बोझ डाले बिना, साप्ताहिक सूचियाँ (अभिव्यक्ति अब सर्वविदित है) को दैनिक सूचियों में विभाजित किया जाता है (यह अभिव्यक्ति भी ज्ञात है) और दैनिक सूचियों को तिथि से एक दिन पहले शाम 4:15 बजे बार रूम में भेजा जाना आवश्यक है। सुनवाई, सोमवार की सूचियों को छोड़कर, जो पिछले शनिवार को दोपहर 12 बजे बार रूम को प्रदान की जाती हैं। किसी दिन के अंत तक नहीं पहुंचने वाले किसी भी मामले को आम तौर पर अगले दिन की सूची में सबसे ऊपर रखने की आवश्यकता होती है और इसी तरह, एक सप्ताह में न्यायालय की बैठक के अंतिम दिन के अंत तक नहीं पहुंचने वाले किसी भी मामले को अगले दिन की सूची में सबसे ऊपर रखा जाना आवश्यक होता है। सामान्यतः अगले सप्ताह की सूची में शीर्ष पर रखा जाता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के आपराधिक अपीलकर्ता के वकील और जेल से प्राप्त मामले में नियुक्त एक

न्याय मित्र अदालत के साथ सीधे संचार में हैं और अपना फैसला प्राप्त करने के लिए मौजूद हैं। तदनुसार, वह अंदर माना जाता है कि अपने मुवक्किल को अदालत के फैसले से अवगत कराने के लिए उसके साथ सीधा संवाद करें, जिससे अवगत कराने में ज्यादा समय नहीं बल्कि मुश्किल से ही उचित समय लगना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 388 के तहत, जब अदालत के फैसले को नीचे की अदालत को सूचित किया जाता है, तो इसमें उचित समय भी शामिल होता है और साथ ही निचली अदालत को यह सूचना भी दी जाती है कि दोषी के जमानत आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दोषी को दोबारा गिरफ्तार करने का जोखिम उठाता है, जो इस अदालत में अपनी अपील या पुनरीक्षण खो चुका है। यह पाते हुए कि इस संबंध में समय की देरी है, इस न्यायालय ने 14 दिसंबर, 1984 को, पत्र संख्या 32352 गज द्वारा II/X.C. 18 ने हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे उन आरोपियों की दोबारा गिरफ्तारी के मामलों में अधिक सावधानी बरतें जो जमानत पर हैं और जिनकी अपील उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। न्यायालय मशीनरी जो भी गति प्राप्त करना चाहे, आवश्यक प्रक्रियाओं में उचित समय लगेगा और इसमें शामिल होने की संभावना भी है। लेकिन इससे पहले कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इस न्यायालय की सूचना प्राप्त होने पर, पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी करने का उपक्रम करे और अपनी प्रक्रिया को गति दे, दोषी से यह अपेक्षा करना उचित है कि वह स्वेच्छा से जेल अधिकारियों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट के फैसले तक आत्मसमर्पण कर दे। तभी यह कहा जा सकता है कि उसने समय पर और स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह सजा में छूट का लाभ उठा सके, जो उसने अर्जित किया होता यदि वह जेल में होता और जमानत पर नहीं होता, जब राज्यपाल या

मंत्री भुगतान करते। उस जेल का दौरा, जहां उसे कैद रखा जाना था। जब इसे अदालत के फैसले के साथ रखा जाता है, तो मुझे सरकारी आदेशों, अनुलग्नक आर-1 और आर-2 की भावना, इरादे और उद्देश्य को प्रभावित करने का यही एकमात्र तरीका लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को मिलाने का यही एकमात्र तरीका है क्योंकि इन दोनों को समानांतर धाराओं में चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इनका संगम होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ।

(8) अब मामले की योग्यता पर आते हुए, आदेश (अनुलग्नक आर-1) का बंदी के लिए कोई फायदा नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया था, एक भी दिन की सजा भुगतने बिना, उन्हें 22 अक्टूबर, 1981 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था और उनकी 22 दिसंबर, 1982 को सत्र न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी। आदेश (अनुलग्नक आर-1) इस प्रकार वह बंदी के मामले में आकर्षित नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से इस स्थिति को स्वीकार कर लिया और निरस्त कर उस संबंध में अपना दावा किया। अन्यथा भी, दावा अधिकतम 15 दिन तक हो सकता है, 60 दिन तक नहीं, जैसा कि दावा किया गया है, क्योंकि सज़ा दो साल से कम थी। लेकिन वह अब मुद्दे से परे है। ऑर्डर की शर्तें (अनुलग्नक आर-2) प्रथम प्रभाव पर बंदी पर लागू होंगी, क्योंकि जेल मंत्री की यात्रा की तारीख पर, बंदी को 32 दिन की सजा काटने के बाद इस न्यायालय के आदेशों के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अब 4 महीने की छूट का दावा करने के रास्ते में स्वैच्छिक और समय पर आत्मसमर्पण की बाधा खड़ी है। पुनरीक्षण याचिका 14 फरवरी, 1984 को खारिज कर दी गई और संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले के परिणाम और जमानत आदेश रद्द करने के बारे में इस न्यायालय द्वारा 22 मार्च, 1984 को जारी

पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। उम्मीद थी कि यह पहुंच जाएगा। संबंधित न्यायालय द्वारा कुछ दिनों में पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की संभावना है। यह स्वीकृत स्थिति है कि गिरफ्तारी वारंट के तहत, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 मार्च, 1985 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस तारीख को बंदी की गिरफ्तारी को, किसी भी तरह से और पहले बताए गए कारणों से, बहुत कम समय पर या स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, बंदी अपने आचरण से 3 अक्टूबर, 1983 के आदेश (अनुलग्नक आर-2) के वातानुकूलित विशेष छूट को उचित रूप से अर्जित करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप उसे कारावास की असमाप्त सजा भुगतनी होगी।

(9) निर्णय समाप्त करने से पहले, हरियाणा सरकार के कारागार महानिरीक्षक को दिनांक 1/14 जनवरी, 1985 को लिखे पत्र (अनुलग्नक आर-3) पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर राज्य द्वारा जोर दिया गया था, जिसमें पैराग्राफ 637 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। पंजाब जेल मैनुअल में प्रावधान है कि जो दोषी जमानत पर हैं और जिनकी सजा निलंबित कर दी गई है, उन्हें छूट प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसे प्रतिवादी द्वारा बंदी के दावे के पूर्ण उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दूसरी ओर, बंदी की ओर से यह दलील दी गई थी कि उसके पैराग्राफ 5 में विशेष रूप से इन निर्देशों के जारी होने से पहले कैदियों को दी गई छूट को शामिल नहीं किया गया है और उन्हें जब्त नहीं किया जाना चाहिए, और याचिकाकर्ता को पहले से ही दी गई ऐसी छूटें लागू रहेंगी। जहां तक छूट प्रणाली के कामकाज का संबंध है, ये निर्देश अच्छे हैं, जिसका दायरा पहले बताया जा चुका है। लेकिन ये निर्देश किसी भी तरह से संविधान की धारा 161 के तहत प्रयोग की गई राज्य सरकार की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। यहां वह प्रश्न नहीं

उठता है। इसी प्रकार, निर्देश जारी करने से पहले छूट के पहले अनुदान को जल करने की रोक (अनुलग्नक आर-3) को पुरस्कार योग्य एक के छठे भाग तक कम की गई अधिकतम छूट के आलोक में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार इन निर्देशों का किसी भी पक्ष के लिए कोई फायदा नहीं है।

(10) निष्कर्ष निकालने के लिए, यह माना जाता है कि जमानत पर रहते हुए एक कैदी अनुपस्थिति में प्राप्त जेल की सजा के प्रति विशेष छूट का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि वह स्वेच्छा से और समय पर पुनर्गिरफ्तारी का वारंट जारी होने से पहले खुद को अदालत या जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देता है।

(11) उपरोक्त कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा